भारत सरकार

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्याः 4558

उत्तर देने की तारीख 20 अगस्त, 2025 (बुधवार)

29 श्रावण, 1947 (शक)

प्रश्न

पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास हेतु सकल बजटीय सहायता का दस प्रतिशत

4558. श्री दिलीप शइकीयाः

क्या **उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार यह सुनिश्चित करती है कि सभी गैर-छूट प्राप्त केंद्रीय मंत्रालय/विभाग अपने सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) का कम से कम दस प्रतिशत पूर्वोत्तर क्षेत्र (डीओएनईआर) के विकास के लिए खर्च करें, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या दस प्रतिशत सकल बजटीय सहायता योजना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए अपने व्यय के लक्ष्यों को पूरा करने में चुनौतियों का सामना कर रहे मंत्रालयों के साथ सहयोग और समन्वय के लिए कोई अलग समर्पित तंत्र स्थापित किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए व्यय में पारदर्शिता में सुधार लाने के लिए दस प्रतिशत सकल बजटीय सहायता योजना पोर्टल के आरम्भ के प्रभाव का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास राज्य मंत्री

(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) और (ख) गैर-छूटप्राप्त मंत्रालयों/विभागों/संगठनों (एमडीओ) द्वारा केंद्रीय क्षेत्र और केंद्र प्रायोजित स्कीमों के दस प्रतिशत सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) तंत्र के अंतर्गत व्यय की निगरानी उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा की जाती है। व्यय विभाग के 05 मई 2017 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए निर्धारित दस प्रतिशत जीबीएस के उपयोग का आकलन करने के लिए सभी गैर-छूटप्राप्त मंत्रालयों/विभागों के साथ नियमित रूप से त्रैमासिक समीक्षा बैठक आयोजित की जाती है। त्रैमासिक समीक्षा बैठकों के दौरान, एमडीओ द्वारा उठाए गए किसी-भी पूर्वोत्तर राज्य सरकार के मुद्दे की समीक्षा और उसका समाधान भी किया जाता है।

(ग) दस प्रतिशत जीबीएस तंत्र के अंतर्गत व्यय हेतु निगरानी पोर्टल में सभी गैर-छूटप्राप्त एमडीओ की डेटा प्रविष्टि और व्यय शामिल होता है। इससे त्रैमासिक समीक्षा बैठकों के दौरान व्यय की समयबद्ध और तत्समय समीक्षा करने में मदद मिलती है। वर्ष 2014-15 के दौरान गुणात्मक व्यय 24,819.18 करोड़ रुपये और वर्ष 2023-24 में 1,02,749.00 करोड़ रुपये था। पिछले 11 वर्षों में अर्थात वर्ष 2014-15 से वर्ष 2024-25 तक 6.11 लाख करोड़ रुपये का व्यय हुआ। इस व्यय से स्थायी संपत्ति का निर्माण हुआ है, जिससे रेल, सड़क और हवाई संपर्क बढ़ा है और स्वास्थ्य, शिक्षा, जल एवं विद्युत जैसे क्षेत्रों में सुधार हुआ है।

*****